भारतका राजपत्र The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 565]

No. 565

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2005/ज्येष्ठ 17, 1927 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2005/JYAISTHA 17, 1927

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

का. आ. 773(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''दीनदार अंजुमन'' को विधि विरुद्ध संगम घोषित कर दिया है।

और उक्त घोषणा संख्यांक का.आ. 672(अ), तारीख 17 मई, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, ठप-खंड (ii), तारीख 17 मई, 2005 में प्रकाशित की जा चुकी है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि वे सभी शक्तियां, जो उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य हैं, पूर्वोक्त संगठन के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी।

> [फा. सं. 14017/9/2005-एन आई-III] ए. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

S. O. 773(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government have declared the "Deendar Anjuman" as an unlawful association;

And whereas, the said declaration has been published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th May, 2005 vide number S. O. 672(E), dated the 17th May, 2005;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby directs that all the powers which are exercisable by it under Sections 7 and 8 of the said Act shall be exercised also by the State Governments and the Union territory Administrations in relation to the aforesaid unlawful organisation.

[F. No. 14017/9/2005-NI-III]

A. K. JAIN, Jt. Secv.

1724 GI/2005